

MR. SPEAKER: Now, we come to amendments. Mr. Yadav, are you pressing your amendment?

श्री युवराज देव नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपना संशोधन वापस लेने की प्रनुमति चाहता हूँ।

(The Amendment No. 1 was by leave, withdrawn.)

श्री राम किशन : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से अपना संशोधन वापस लेने की प्रनुमति चाहता हूँ।

The Amendments No. 3 was by leave withdrawn)

MR. SPEAKER: Mr. Yuvraj, are you pressing your amendment?

SHRI YUVRAJ: Yes.

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 9th May, 1978."

The motion was negatived.

MR. SPEAKER: Now, we come to the Bill. The question is:

"That the Bill to provide interest for the demonetisation of certain high denomination bank notes and for matters connected therewith or incidental thereto, be taken into consideration."

The motion was adopted.

MR. SPEAKER: There are no amendments. The question is:

"That clause 2 to 15 stand part of the Bill."

~~The motion was adopted.~~

Clauses 2 to 15 were added to the Bill

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Schedule stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Schedule was added to the Bill. Clause 1, the Enacting Formula, the Preamble and the Title were added to the Bill.

SHRI H. M. PATEL: I beg to move:

"That the Bill be passed."

MR. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

THE MINISTER OF STEEL AND MINES (SHRI BIJU PATNAIK): Sir, I have a request to make to the House. There are two more Bills to be passed. The Rajya Sabha is adjourning tomorrow. I would request the hon. Members to agree that the sitting of the House may be extended today to pass the remaining two Bills according to the list of Business.

SHRI K. LAKKAPPA (Tunkur): What is the hurry about it? You send it to the Joint Committee. We have to go deep into it.

SHRI BIJU PATNAIK: I am only requesting you to extend the time of the House.

17.37 hrs.

HINDUSTAN TRACTORS LIMITED (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) BILL.

MR. SPEAKER: We now take up the next item; Shri George Fernandes.

उद्योग मंत्री (श्री वार्ध कर्मान्वित)
अबन्ध महोदय, मैं आपकी भाज्ञा से प्रस्ताव*
करता हूँ :

“कि जन साधारण की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये अत्यावश्यक माल का उत्पादन जारी रखना सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये हिन्दुस्तान ट्रेक्टर लिमिटेड, विश्वामिठी, बड़ोदरा के उपकरणों के अर्जन और अन्तरण का तथा उससे सम्बन्धित या उसके आनु-वंशिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

इस विधेयक पर विवाद की कोई गुजाइश हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है।

DR. VASANT KUMAR PANDIT

(Rajgarh): Sir, on a point of information.

The matter in sub judice, it is already in the court and applications have been made.....

MR. SPEAKER: In legislative measures, there is no question of sub judice at all. The Parliament is supreme.

श्री वार्ध कर्मान्वित : मैं जैसा कह रहा था, यह ऐसा विधेयक है जिस पर कोई खास विवाद की गुंजायश नहीं है। 1973 के मार्च में आई० डी० आर० ऐक्ट के अन्तर्गत, हिन्दुस्तान ट्रेक्टर लिमिटेड जो बड़ोदरा में कारखाना है, ट्रेक्टर बनाने वाला, उसको सरकार ने अपने हाथ में लिया था और गुजरात एग्री एण्डस्ट्रीज कारपोरेशन, जो सरकारी क्षेत्र में बनी हुई संस्था है उस संस्था के हाथों में इसको चलाने की जिम्मेदारी दी थी। उसके बाद अब पांच साल पूरे हो रहे हैं। इन पांच सालों में गुजरात एग्री एण्डस्ट्रीज कारपोरेशन ने इस कारखाने को

चलाते हुए इसकी स्थिति में काफी सुधार करने में कामयाबी पाई है। जिस साल इसको सरकार ने अपने हाथों में लिया उस साल इस कारखाने में कुल 80 लाख रुपया का घाटा था। पिछले साल उस घाटे को लगभग 8 लाख पर लाने में गुजरात एग्री एण्डस्ट्रीज कारपोरेशन को कामयाबी मिली। और इस साल पहली बार कई वर्षों के बाद यह कारखाना मुनाफा दिखायेगा, ऐसा भ्रवाज है। मुनाफा बहुत ज्यादा नहीं होगा लेकिन लगभग एक लाख रुपए का मुनाफा इस साल पहली बार इस कारखाने को होगा।

बीमार प्रवस्था में इस कारखाने को सरकार ने लिया था, जिस तरह से दूसरे बीमार उद्योगों को सरकार को लेना पड़ता है। इस कारखाने को लेने से पहले इस की जांच हुई थी, जिस तरह से दूसरे कारखानों की जांच होती है और उन जांच में एक बात यह भी दिखाई दी कि इस कारखाने को जिस तरह में चलाया जा रहा था, वह ठीक नहीं था। इस तरह की स्थिति इस देश में हर रोज दिखाई देनी है कि कारखाने को चलाने का ढंग ठीक न होने के कारण उसमें बीमारी आ जाती है और इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी को परेशानी होती है, तो वह मजदूरों के साथ होती है। अगर कभी-कभी हमारे सामने ऐसी समस्या भी खड़ी हो जाती है कि अगर किसी बीमार उद्योग को ले लिया जाय और उसके बाद सब लोगों की मेहनत के चलते, जिसमें मजदूरों का सबसे ज्यादा योगदान होता है, उस कारखाने को सुधारने का काम सफल हो जाये, तो पांच साल के पूरे होते ही जो पुराने मालिक होते हैं, वे फिर भागे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब कारखाना ठीक से चलने लगा है, हम भी अब इसको ठीक से चला सकते हैं, लेकिन इस मामले में अनुभव कुछ और ही होता है। जो मदन में उस तरह बैठने वाले लोग हैं, वे भी ऐसा कर चुके हैं और हम भी कर रहे हैं। इसलिये जब मैं इन विधेयक

*Moved with the recommendation of the President.

को सदन के सामने ला रहा हूँ—तब मैं इस बीच को महसूस करता हूँ—काफ़ी लोगो का भी इस बात का आग्रह रहा—कि वह कारखाना बूँकि अब नई स्थिति में पहुँच रहा है और अगले पाँच वर्षों में हम इस का औषविक्य देख रहे हैं—वह भी काफ़ी प्रगति करने वाला दिखाई दे रहा है, जैसे पाँच साल के पहले हम कारखाने का कुल टर्न-ओवर 2 करोड़ रुपये सालाना था, जो अब 8 करोड़ रुपये से ज्यादा है और अगले पाँच सालों का जो हमने प्रोज़ेक्शन किया है, उसके चलते पाँच वर्ष के बाद इसका टर्न-ओवर लगभग 23 करोड़ रुपये तक आ जायगा—इन सारी बातों को दृष्टि में रखते हुए सरकार इस नतीजे पर पहुँची कि इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय मैंने पहले कहा है कि इस पर कोई वाद-विवाद की गुंजाइश नहीं है। ऐसा कहने के पीछे एक खास कारण भी है—इसके राष्ट्रीयकरण का पहला प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास अक्टूबर, 1976 में आया था। उस समय गुजरात में राष्ट्रपति शासन था और केन्द्र में कांग्रेस सरकार थी, यानि वही सरकार थी जो वहाँ राष्ट्रपति शासन का चला रही थी। तो उस समय राज्य की तरफ़ से केन्द्र के पास यह प्रस्ताव आया कि कारखाने का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये, क्योंकि हमारा कोई तरीका इस कारखाने को चलाने का नहीं है। उस प्रस्ताव के आने के कुछ महीने के बाद गुजरात में कांग्रेस दल की सरकार बन गई और केन्द्र की कांग्रेस सरकार ने, बूँकि पहले जो प्रस्ताव आया था, वह राष्ट्रपति शासन के चलते आया था, वहाँ के गवर्नर, उनके एडवाइज़र और वहाँ का जो उद्योग विभाग है, उसकी तरफ़ से आया था, यह तय किया कि अब चूँकि वहाँ नई सरकार बन गई है, इस लिये हम उनकी गय का जानना चाहेंगे, यह कह कर उस प्रस्ताव का फरवरी, 1977 में गुजरात राज्य का वापस भेज दिया। वहाँ

इस पर पुनर्विचार हुआ और उस पुनर्विचार के बाद जो प्रस्ताव हमारे पास आया . . .

SHRI VAYALAR RAVI (Chirayinkil) Was it returned by the Government?

SHRI GEORGE FERNANDES: The first proposal came in October 1976 from the Gujarat Government suggesting nationalization of this unit. At that time, Gujarat was under President's rule. In February 1977, that is before the last general elections, when the Congress Ministry was formed in Gujarat; Bahubhai Patel went out in March, 1976; in October, 1976 there was President's rule, a month or two thereafter, a popular Ministry was installed there.

SHRI VAYALAR RAVI: Shri Madhavsinh Solanki was the Chief Minister

SHRI GEORGE FERNANDES: Yes, the Central Government at that point of time referred the matter back to the State Government with a suggestion that since this proposal came at the time of the President's rule, we would now like to have the opinion of the new Government. Further changes came about thereafter in the Government and we had the Gujarat Government later on interact with the Central Government and tell us again that the Gujarat Government stood by its earlier proposal to nationalise this unit

मगर केन्द्र और गुजरात राज्य दोनों में जो बातचीत हुई, उसके सन्दर्भ में और विशेष कर स्टेट बैंक आफ इण्डिया से, जिसके दस

[श्री जार्ज फर्नान्डिस]

कारखाने में कई करोड़ रुपये लग गये हैं—
 डार्ड करोड़ रुपये स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया के
 इस कारखाने में फसे हुए हैं—इस मामले पर
 काफी चर्चा हुई है और उम चर्चा के चलते
 एक नई जांच इस कारखाने के बारे में फिर से
 करने में आ गई और उम जांच के हाने के बाद
 यह प्रस्ताव बहुत मजबूत तौर पर गुजरात
 सरकार में आ गया और गुजरात सरकार इस
 बात पर विस्तृत प्रतिवेदन इस कारखाने
 का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। हमने गुजरात
 सरकार के इस प्रस्ताव का स्वीकार करने का
 ब्यापार हम यह मानते हैं कि कारखाने का
 राष्ट्रीयकरण करने में इस कारखाने में बने
 वाली चीजा का, इस कारखाने में काम करने
 वाले मजदूरों का या किसी का नुकसान
 सकता है।

एक आखरी बात में इस मामले पर और
 कहा जायगा और यह यह है कि जब निजी
 क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र वगैरह पर वचन
 डाली है, ना कोन कारखाने का बनाया
 मैंने जेम्स फ्रिम का स्वीकार किया वह बहम
 चलती है तब अधिराज्य हम उम बात को
 भूत जान है कि उम। उम पंजी पिंग की
 लगी हुई है और यह मानते हैं कि निजी किसी
 एक परिवार के हाथ में या जिन किसी पर
 गिराह या समूह के हाथ में वह उद्योग जाता
 है, मारी र्जी उम परिवार या उस समूह की
 ही उम कारखाने में पडी हुई है। यह बहुत
 बडी गलतफहमी है जैसे यह कारखाना एक
 परिवार के नाम में है और इस कारखाने में
 वह परिवार पहले जुडा हुआ था मगर जो
 इतनी मारी पूजा इस कारखाने में लगी है,
 उममें से केवल 17 प्रतिशत ही उम परिवार
 की र्जी है और 83 प्रतिशत पूजा सार्वजनिक
 सस्थाओं को जैसे एन० आई० सी० यू०
 टी० आई०, आरियेन्टल फायर एण्ड जनरल
 इन्शोरेंस और दूसरी पब्लिक सेक्टर अन्डर-
 टेकिंग की है। कुल मिला कर 83 प्रतिशत
 पूजा उनकी हममें पडी है। इसलिए जव भी

किसी एक सस्था को लिया जाता है और किसी
 कारणवश उसको लिया जाता है, तब यह
 चर्चा होती है जैसे हम किसी व्यक्ति का
 परिवार या किसी समूह पर हला बोलने जा
 रहे हैं। इसमें कोई खास तथ्य नहीं है और इस
 कारखाने के संदर्भ में मैं यह बात इसलिए
 दोहरा रहा ह क्योंकि काफी चर्चा,
 काफी बहम सार्वजनिक तौर पर और
 अन्य तौरों पर इन बात पर हुई थी। इसलिए
 मैंने इन बात का साफ बयान जरूरी समझा।
 मुझे उम बात में श्री. ग्रिध, कुछ कहने
 की जरूरत महसूस नहीं है। मैं और मेरी
 प्रार्थना है कि यह सदन उम विषय पर सर्व-
 सम्मति से स्वीकार करे।

MR SPEAKER Motion moved

'That the Bill to provide for the
 acquisition and transfer of the
 undertakings of Hindustan Tractors
 Limited Vishwamiti, Vadodara,
 for the purpose of ensuring the
 continuity of production of goods
 which are vital to meet the needs
 of the general public and for
 matters connected therewith or
 incidental thereto, be taken into
 consideration'

There are some notices of amend-
 ments. Those members who want to
 move them may please do so now

SHRI HUKMDEO NARAIN
 YADAV (Madhubani) I beg to
 move

"That the Bill be circulated for
 the purpose of eliciting opinion
 thereon by the 15th June, 1978" (1)

DR VASANT KUMAR PANDIT
 (Rajgarh) I beg to move

"That the Bill be circulated for
 the purpose of eliciting opinion
 thereon by the 15th July, 1978" (3)

SHRI VINAY PRASAD YADAV
 (Saharsa) I beg to move,

'That the Bill be circulated for
 the purpose of eliciting opinion
 thereon by the 30th June, 1978" (5)

श्री श्रीमन् राज (बीरकपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए बड़ा हुआ हूँ। आप जानते हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की ओर से बराबर राष्ट्रीयकरण के बिलों का समर्थन किया गया है। फर्नानडिस साहब इससे पहले भी जो बिल राष्ट्रीयकरण के बारे में लाये थे, हमने उनका भी समर्थन किया था। इस बिल के बारे में मैं ज्यादा बहस में नहीं पड़ूंगा क्योंकि वक्त कम है।

हमारे जितने बीमार कारखाने हैं उनको कैसे हाथ में लिया जाए, इसके बारे में काफी धारणा बनाई है। मैं इस सम्बन्ध में दो-एक धारणाएं फर्नानडिस साहब के सामने रखना चाहता हूँ। मेरी पहली धारणा तो यह है कि जब कोई कारखाना केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में लेती है, या उसका राष्ट्रीयकरण करती है तो उसे केन्द्रीय सरकार अपने आप ही उस कारखाने को चलाती है, अपने ही डायरेक्टर्स नियुक्त करती है। इसलिए मेरे मन में इसके परिचालन के बारे में शंका है। जब इस कारखाने का परिचालन राज्य सरकार पर छोड़ा जा रहा है तो अगर इसके पीछे कोई मियासत है, यह मुझे धारणा है। क्योंकि गुजरात में बाबू भाई की मिनस्ट्री है और वह मिनस्ट्री फर्नानडिस साहब की अपनी पार्टी की मिनस्ट्री है। इसलिए यह शंका मेरे मन में है। (अध्यक्ष) क्या वहाँ बाबूभाई की मिनस्ट्री नहीं है? क्या वह कारखाना उसके हाथ में नहीं जा रहा है? क्या यह सब सही है?

दूसरे फर्नानडिस साहब को ये रा कहना यह है कि इसके पहले भी उन्होंने कारखाने अपने हाथ में लिये हैं। उन बीमार कारखानों के जो छोटे छोटे क्रेडिटर्स होते हैं उनको पैसा मिलने में बहुत मुश्किल हो जाती है। बड़े मालिक तो अपना कम्पेन्सेशन ले जाते हैं लेकिन छोटे लोगों को पैसा मिलना मुश्किल हो जाता है। वेस्ट बंगाल में बहुत से बीमार कारखाने थे और उन्हें कुछ लोग माल सप्लाय किया करते थे। उनके सामने यह समस्या आ रही है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय

से अनुरोध करूंगा कि वे इस बारे में ध्यान दें। यह बात मैं इस कारखाने के बारे में नहीं कह रहा हूँ। यह सुझाव मैं जनता पार्टी का जो इंडस्ट्रियल पालिसी रिजोल्यूशन है, उस के सम्बन्ध में दे रहा हूँ। आपने इस कारखाने का राष्ट्रीयकरण किया इसके लिए तो मैं आपको बधाई दूंगा लेकिन बीमार कारखानों के सम्बन्ध में आप जो इंडस्ट्रियल पालिसी प्रकृतियार करें, उसमें इस बात का ध्यान रखें।

आपकी जो इंडस्ट्रियल पालिसी है, उसमें लिखा है—

“While Government cannot ignore the necessity of protecting the existing employment but the cost of maintaining such employment will also be taken into account.”

फर्नानडिस साहब इस स्टेटमेंट में किन्तु आ गया है। आप जब बम्बई में थे तो कहते थे कि इस कारखाने को लेना है, उस कारखाने को लेना है। लेकिन अब इस स्टेटमेंट में किन्तु आ गया है। जब कांग्रेस सरकार थी, तब हमने देखा था कि बाहर से इतना प्रेशर रहता था कि इतना पैसा खर्च करके क्यों बीमार कारखाना लिया जा रहा है। इसलिए फर्नानडिस साहब को ये सारी बातें जाननी होंगी और सोचना होगा कि जो बीमार कारखाने आप ले रहे हैं वे किस कंसीड्रेशन से ले रहे हैं। पोलिटिकल कंसीड्रेशन से ले रहे हैं। या इकोनॉमिक कंसीड्रेशन से ले रहे हैं? जो कारखाने आप ले रहे हैं उनमें कितने लोगों को नौकरी मिलेगी। ये सब बात सोचने की है।

ये मेरे तीन सुझाव हैं। मैं फर्नानडिस साहब को इस बिल को लाने के लिए बधाई देता हूँ और इस बिल का पूरे दिल से समर्थन करता हूँ।